मूल्य : 25 रुपये
जुलाई - सितम्बर, 2022

वर्ष : 11, अंक : 45

नर्मदा समग्र

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा समग्र द्वारा आयोजित एवं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं गृह वाटिका निर्माण करने की प्रशिक्षण कार्यशाला' में आये प्रशिक्षणार्थियों के साथ पीपल, मौलश्री, गूलर के पौधों का भोपाल स्मार्ट सिटी उद्यान में रोपण किया।
संस्था के सचिव ने 'नर्मदा समग्र' त्रैमासिक पत्रिका व भारत के प्रमुख औषधीय पौधे पर आधारित पुस्तिका भेंट की।

नर्मदा समग्र

का त्रैमासिक प्रकाशन

वर्ष : 11
अंक : 45
माह : जुलाई - सितम्बर 2022

संस्थापक संपादक
स्व. अनिल माधव दवे

संपादक
कार्तिक सप्रे

संपादकीय मण्डल
डॉ. सुदेश वाघमारे
संतोष शुक्ला

आकल्पन
संदीप बागड़े/दीपक सिंह बैस

मुद्रण
नियो प्रिंटर्स
17-बी-सेक्टर,
औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल

सम्पर्क
'नदी का घर'
सीनियर एम.आई.जी.-2, अंकुर कॉलोनी,
शिवाजी नगर, भोपाल-462016

E-mail : narmada.media@gmail.com

@narmadasamagra @narmada_samagra
@narmadasamagra @narmadasamagra
@narmadasamagra www.narmadasamagra.org

इस अंक में .....

पर्यावरण प्रहरी

1. संपादकीय 05
2. शहरी जैव विविधता बचाने का संकल्प लेना होगा... 06
3. मेरे मरने के बाद भी पेड़ न कटे 08
4. उत्तर प्रदेश ने की नदी नीति बनाने की पहल 10
5. छोटी नदियों के लिए नाम के बड़े काम 13
6. पर्यावरण पहरी 15
7. औषधीय पौधों पर प्रशिक्षण कार्यशाला 16
8. नर्मदा अचंल के वृक्ष - अर्जुन, कोहा 20
9. नर्मदा की चट्टाने 21
11. मध्यप्रदेश के रामसर स्थल 22
12. नदियाँ दर्शन का अंग है... 24
13. सहस्त्र डोल - शहडोल 27
14. शोषक नहीं, पोषक है हम 28

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्री करण सिंह कौशिक द्वारा नियो प्रिंटर्स, 17 बी-सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं नदी का घर सीनियर एम.आई.जी.-2, अंकुर कॉलोनी, पारूल अस्पताल के पास शिवाजी नगर, भोपाल-462016 से प्रकाशित।
संपादक : कार्तिक सप्रे। फोन : 0755-2460754

क्या आपके आसपास भी है ऐसा कोई बड़ा-पुराना

"Heritage Tree"

अगर है तो आप भी उसे आलिंगन कर उसका चित्र सोशल मीडिया #HeritageTree हैशटैग का प्रयोग कर, पेड़ का नाम, स्थान, लगभग कितना पुराना है, उससे जुड़ी कोई रोचक बात हो तो अवश्य शेयर करें।

नीम | लगभग 3 फिट व्यास | खलबुजुर्ग घाट (दक्षिण तट खलघाट) के समीप पी.डबल्यू.डी. विश्राम गृह प्रांगण

माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर स्थित ब्राह्मण गांव तहसील ठीकरी जिला बड़वानी जो ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है ! यहां ब्रह्मा जी की तपोस्थली और नर्मदा पुराण में गुप्तेश्वर महादेव का उल्लेख है यहां सुकेश्वर एवं पत्रेश्वर शिव मंदिर है, यह दो पेड़ वड़ (वरगद) के है, जानकारी के अनुसार करीब 150 वर्ष पुराने है।

नर्मदा जी के उत्तर तट पर स्थित नजर वॉस आश्रम खलघाट जिला धार में एक त्रिवेणी जिसमें विशालकाय वट वृक्ष है, इस वृक्ष की गोलाई करीब 3 मीटर है मान्यता है कि श्री गौरीशंकर जी महाराज ने 150 वर्ष पूर्व माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की थी जब कि यह त्रिवेणी रोपित है।

माँ नर्मदा तट त्रिवेणी संगम महाराजपुर जिला मण्डला वरगद का 100 वर्ष से अधिक आयु का वट वृक्ष।

वन्य जीवन में भारतीय दर्शन

वन और वन्य जीवन मनुष्यों को लिए ईश्वर को एक ऐसा उपहार है, जिस पर सम्पूर्ण मानव जाति का अस्तिस्व निर्भर करता है। वन और उनमें रहने वाले जीव-जन्तुओं का मनुष्यों से सदियों से एक प्रकार का विशिष्ट संबंध रहा है। यदि हम भारत के अतीत को खोजें, तो पाएंगे की हमारे देश के इतिहास में लेखकों की रचनाओं में वेदों में प्रकृति और वन्य जीवों के साथ मानव के घनिष्ठ संबंधों का वर्णन हमें जगह-जगह मिलता है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन ही है, जिसमें वनों और उनमें रहने वाले जीव-जन्तुओं के संरक्षण पर जितना ध्यान दिया गया है, उतना शायद ही विश्व की किसी अन्य सभ्यता में दिया गया हो।

वनों में रहने वाले जीव-जन्तुओं से लेकर पेड़-पौधें तक को देवी-देवताओं के साथ जुड़े हैं, जिसके कारण वन्य जीव-जन्तु और पेड़-पौधों, प्राचीन रिति-रिवाजों और धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के द्वारा सम्मान पाते रहे हैं। यही हमारा वन्य जीवन के संरक्षण में भारतीय दर्शन है। भारतीय समाज में वन्य जीवन के प्रति समय-समय पर सम्मान भाव प्रकट करते रहना है, इसका मुख्य मकसद पर्यावरण और वन्य जीवन का संरक्षण करना रहा है। भारतीय दर्शन में प्रकृति के शोषण की बात तो वह सपने में भी नहीं सोची जा सकती और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध ही हमारे धर्म का मर्म रहा है। प्रकृति के दैविक स्वरूप को पूजा जाता रहा है।

लेकिन समय ने करवट बदली और भारतीय मानव शहरीकरण और औद्योगीकरण की और बढ़ने लगा, जिससे मनुष्य का प्रकृति से संपर्क टूटता चला गया। विकास की दौड़ में उसकी यह अनुभूति समाप्त हो गई कि प्रकृति भी एक जीवन्त शक्ति है। मानव विकास की तेज रफ्तार और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की मानसिकता के कारण प्रकृति से दूर होता चला गया। यही कारण है कि भारतीय समाज ने धीरे-धीरे वन्य जीवन को खुद से अलग करता जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि बढ़ते औद्योगिकरण, फैलते शहरों और बढ़ती जनसंख्या के कारण आज वन क्षेत्र घटते चले जा रहे हैं। जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे वनों में रहने वाले जीव-जन्तुओं के जीवन पर पड़ रहा है।

मानवीय गतिविधियों के कारण जीव-जंतुओं एवं कई प्रकार के पेड़-पौधों की कुछ जातियां लुप्त होने की कगार पर है। इसका मुल कारण मानव द्वारा वन्य जीवों के इलाकों में अतिक्रमण है। हम वनों को केवल ऊबड़-खाबड़ धरती, कटीली झाड़ियां समझते हैं, लेकिन हम भूल जाते है कि वनों में रहने वाले जीव, जन्तु और पक्षियों लिए ये झाड़ियां उनका घर हैं। वनों की ऊबड़-खाबड़ भूमि वन्य प्राणियों के लिए उनका आंगन है। हमने यह भूला दिया कि धरती पर जल, जमीन, जंगल जहां मिलते है वहीं पर जीवन का विकास संभव है।

अतः सभी वन्य जीव और मानव जाति किसी न किसी रूप से एक-दूसरे को प्रभावित करते है। वन और वन्यजीव पर्यावरण जगत का आधार है और मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। मानव की प्रकृति पर विजय पाने की लालसा ने संसाधनों को तेजी से नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण तंत्र को असंतुलित कर दिया, जिससे वनों में रहने वाले जीव-जन्तुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है वनों की कटाई के कारण जल-धाराओ, नदियों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, फलस्वरूप पृथ्वी पर उपस्थित प्राणियों के जीवन के साथ ही पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

वन्यजीवन और मनुष्य एक दुसरे के पूरक है, यदि किसी भी प्राणी की संख्या में या किन्हीं विशेष प्रकार के छोटे-बड़े पेड़, औषधीय पौधों में अथ्वा यूँ कहें की जैव विविधता में कमी आती है तो नुकसान सारे पर्यावरण को होता है। इसका मतलब तो यही है कि पर्यारवण के विभिन्न घटकों को होने वाले नुकसान से मानव के अस्तित्व को ही गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। अतः यह बहुत जरूरी है कि हम वन्य जीवन व जैव विविधता की रक्षा के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन को प्राथमिकता दे।

आज की यह आवश्यकता यह है वन्य जीवन के संरक्षण के लिए दूरगामी योजनाओं को बनाए जाए, ताकि लोग वन्य जीवन के मुल्यों को समझे और वन्यजीवों की रक्षा में अपना योगदान दे सके। जिससे मनुष्य प्रकृति से लगाव बनाकर लुप्त होते वन्य जीवों एवं जैव विविधता की सुरक्षा की जिम्मेदारी। □

शहरी जैव विविधता बचाने का संकल्प लेना ही होगा हमें

वर्ष 1992 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील के शहर रिओ में पृथ्वी सम्मेलन के समय जैव विविधता पर वैश्विक मंथन भी हुआ और बाद के वर्षों में कई और सम्मेलन हुए। विश्व समुदाय को यह समझ में आ गया था कि जलवायु परिवर्तन के दौर में व बढ़ते तापमान को रोकने के शाश्वत उपाय ढूंढने होंगे।

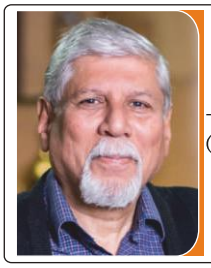

डॉ. अभिलाष खाण्डेकर
(लेखक - वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद् हैं।)

एक काल्पनिक चित्र आपकी नजरों के सामने लाने का प्रयास करें... एक ऐसे शहर का जिसमें ना कोई पेड़-पौधे हो, ना नदी-तालाब हो, ना कोई हरी-भरी पहाड़ी हो और ना हो कोई बाग-बगीचे। सिर्फ मकान, दुकान, मॉल, अस्पताल और कल कारखाने हो।

क्या बिना चिड़ियों की चहचाहट के, या छायादार वृक्षों के या बच्चों के लिए खेलने के बड़े खुले मैदानों के या तालाबों-नदियों से मिलने वाले अमृत तुल्य जल के सिवाय हम मनुष्य प्राणी जीवित रह सकेंगे? आनंदित रह पाएंगे? आपका जो उत्तर होगा, जो सोच होगी वही इस लेख की प्रस्तावना है और वहीं महत्वपूर्ण है। हाँ, इंदौर के पहले सम्मेलन का आयोजन भी इसीलिए किया गया था। उसका थोड़ा विवरण भी यहां दिया गया है जो हम सभी को सोचने व जमीनी स्तर पर काम करने हेतु प्रोत्साहित करेगा ऐसी आशा है।

भारत के बेतहाशा बढ़ते शहर अपनी प्राकृतिक हरियाली एवं परंपरागत पानी के स्त्रोत लगातार खोते जा रहे है और जाने अनजाने में अपने पैरों पर लगातार कुल्हाडी मारे जा रहे है। आम आदमी इसके खतरों से शायद अनजान है। किंतु और अधिक दिन अनजान बने रहने से आप-हम अपने आप को एक घने एवं गहरे गड्ढे की और रोजाना ढ़केलने जा रहे है जहां से निकल पाना असम्भव होगा।

ऊपर वर्णित तालाब, नदियों, वृक्षों की ढेरों अलग-अलग प्रजातियों, या अलग-अलग फूलों और उस पर मंडराने वाली तितलियों, छोटी चिड़ियों व भंवरों तथा घास-फूस आदि इत्यादि को ही जैव विविधता के नाम से संबोधित किया जाता है।

हमारे शहरों में बहुतायत में पाए जाते रहे वृक्ष अब तेजी से कटते जा रहे है, विकास के नाम पर। आमतौर पर शहरों में बडे बगीचे होते थे, कुएं-बावडियाँ थी। गौरेय्या घर के बाहर चहकती थी। गर्मी के मौसम में वातानुकूलित यंत्र हर घर में नही थें। दुःखद पहलू यह है की सब कुछ बड़ी तेजी से और नकारात्मक ढंग से बदल रहा है। इसे आज ही, अब ही रोकना होगा। इसी विषय को लेकर अगस्त माह में इंदौर शहर में देश के पहले राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन का आयोजन द नेचर वालंटियर संस्था द्वारा किया गया था। उद्देश्य साफ था। शहरो को चलाने वाले अधिकारियों, महापौर गण, पार्षद व ठेकेदारों, सिविल इंजीनियर, नगर नियोजकों तथा जिम्मेदार नागरिकों को देश भर से आए विशेषज्ञों ने अपने अनुभव के आधार पर यह बताने की कोशिश की कि कैसे जैव विविधता को बचाया जा सकता है और क्यों प्राथमिकता

के तौर पर बचाया जाना जरूरी है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में यह बातें भी सामने आई की कैसे शहरों के तापमान में पिछले एक दशक से लगातार वृद्धि हो रही है। डब्लूडब्लूएफ की सुश्री अंबिका शर्मा, जैव विविधता प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रमुख डॉ वी.बी. माथुर, तथा अन्य वक्ताओं जैसे अतुल श्रीवास्तव, डॉ. हितेश वैद्य, कौस्तुभ रिषी, लोकेंद्र ठक्कर तथा नगर नियोजन विशेषज्ञ डॉ. पी.एस.पी.एन. राव आदि ने अपने-अपने सत्रों में शहरो के हालात बखान किये और जैव विविधता संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को अधोरेखित किया और आगामी खतरों से आगाह किया।

संक्षिप्त इतिहास

भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहली दफे जैव विविधता संरक्षण का कानून 2002 में बनाया। उसके पश्चात चेन्नई में राष्ट्रीय प्राधिकरण बना और सभी राज्यों में अपने-अपने बोर्ड गठित हुवे। नियम भी बने। संकल्पना यही थी कि शहरों की आबो-हवा अच्छी रहे, तापमान नियंत्रित रहे, शहर हरे-भरे

को रोकने के शाश्वत उपाय ढूंढ़ने होंगे। जैव विविधता संरक्षण उन उपायों में से एक प्रभावशाली उपाय माना गया था। इधर भारत मे भी मामला कूर्म गति से आगे बढ़ रहा था। शहरों की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा था।

किन्तु इंदौर सम्मेलन ने उस जड़ता को तोड़ने का बड़ा काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। इंदौर से पूरे देश के सरकारी अफसरों व पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दृढ़ता से एक संदेश गया कि शहरों को शाश्वत रखना हो तो जैव विविधता को हर हाल में बचाना होगा। इसमें स्थानीय सरकार, पर्यावरणविद व आम नागरिकों की भी भूमिका होगी। सम्मेलन के अंत में 'इंदौर घोषणा पत्र' का विमोचन भी किया गया जिसके पालन से हमारे शहर भविष्य में बच सकेंगे। यह घोषणा पत्र अपनी तरह का पहला दस्तावेज है जैव विविधता संरक्षण को ले कर।□

रहें, पानी से भरपूर रहें और लोग शान्ति से अच्छा जीवन यापन कर सकें। उक्त कानून का एक और बड़ा उद्देश्य यह भी था कि देश भर में जैव विविधता के रजिस्टर बनाए जाए व स्थानिय वनस्पतियों, पक्षियों, जड़ी बूटियों आदि का संवर्धन हो व उनका रेकार्ड बनाया जाए जिससे भविष्य की पीढ़ियों को भी इसका ज्ञान हो व फायदे मिलें।

किन्तु दो दशक पश्चात भी वह कानून बहुत अधिक सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण रहे। भारत में वैसे भी कानूनों के कड़क रूप में पालन होंने का प्रचलन नहीं है जो की मै दुःखद मानता हूँ। इसे बदलना होगा।

वर्ष 1992 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील के शहर रिओ मे पृथ्वी सम्मेलन के समय जैव विविधता पर वैश्विक मंथन भी हुआ और बाद के वर्षो में कई और सम्मेलन हुए। विश्व समुदाय को यह समझ में आ गया था कि जलवायु परिवर्तन के दौर में व बढ़ते तापमान

मेरे मरने के बाद भी पेड़ न कटे

उत्तराखंड के नाई ग्राम, नाई ढोगचमा ब्लॉक, ओखगढ़ा जिला नैनीताल वाले चंदन सिंह नायाल पिछले एक दशक से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने आपको समर्पित किए हुए हैं। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई के समय से ही पौधारोपण शुरू कर दिया था। अपने अथक परिश्रम से उन्होंने अपने गांव के नजदीक में तीन हेक्टर का बांस और अन्य पौधों का जंगल खड़ा कर दिया है। हम उनके प्रकृति के प्रति समर्पण को इस प्रकार समक्ष सकते है कि उन्होंने अपने शरीर को स्थानिय मेडिकल कॉलेज को दान में देने का निर्णय किया है, क्योकि वह अपने मरने के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए किसी पेड़ को कटवाना नहीं चाहते इस प्रकार की पर्यावरण को समर्पित विभूति से नर्मदा समग्र पत्रिका के संपादकिय मंडल सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार संतोष शुक्ला जी द्वारा टेलीफोन सक्षात्कार के अंश.....

प्रश्न - आपको पर्यावरण को लेकर काम करना चाहिए इस भाव की जागृति आपके अंदर कब हुई ?

उत्तर - मेरी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई थी और छुट्टियों में गांव आ जाता था, उस समय जब हमारे गांव के आस-पास चीड़ के जंगलों में अक्सर आग लग जाया करती थी। तब गांव के सभी लोग जंगल में आग बुझाने के लिए जाते और मैं भी अपने पिता जी के साथ जंगल की आग बुझाने के लिए उनके साथ जाता था। वही से मेरे अंदर पर्यावरण और वृक्षो के संरक्षण करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। जब जंगल में आग लगती थी तब अक्सर छोटे-बड़े पेड़-पौधे जैसे काफल, बुराख भी जल जाते थे, मेरे मन में उन पौधों को बचाने के बारे में अक्सर विचार आते थे। इसके बाद से मैंने जंगल से इन वृक्षों को लाकर अपने घर और खेत में लगाना शुरू कर दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करते हुए भी मैं पर्यावरण के लिए स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ पौधारोपण का कार्य करता रहा। बाद में मैंने अपनी नौकरी छोड़ कर अपने आपको प्रकृति के लिए समर्पित होकर कार्य करने का निर्णय लिया।

प्रश्न - आपको कभी ऐसा नहीं लगा की आपको भी एक संस्थान या एनजीओ बना कर पर्यावरण संरक्षण के कार्य को गति देना चाहिए ?

उत्तर - मेरे काम से प्रभावित कई लोगों ने मुझे एनजीओ बना कर पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने के लिए कहां लेकिन हमारे यहां पहाड़ो पर लोगों को एनजीओ के प्रति विश्वास कम है इसका मुख्य कारण शहरी क्षेत्र से आए विभिन्न प्रकार एनजीओ द्वारा किए गए गलत कार्य है। इसलिए मेरा मानना है कि समाज के साथ मिलकर काम करना अच्छा है, बिना किसी संस्था को बनाए हुए। इसलिए मैने गांव के लोगों के साथ मिलकर

पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया इसका परिणाम यह हुआ कि गांव के लोगों द्वारा मुझे तन, मन, धन सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त होने लगा। और इसका प्रभाव यह हुआ कि गांव के लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनेपन का भाव और मेरे कार्य के प्रति लगाव पैदा हुआ।

प्रश्न - पौधारोपण के अलावा आप पर्यावरण संरक्षण के लिए और क्या गतिविधि करते है ?

उत्तर - नौकरी छोड़ने के बाद जब मैने अपना सारा ध्यान गांव में पर्यावरण संबंधित समस्या पर देना शुरू किया, तब मेरा ध्यान पानी की समस्या पर भी गया। मेरे गांव में 40 परिवार रहते हैं, और यहां पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चत करने के लिए कोई भी सरकारी योजना नहीं है और न ही जल संरक्षण का कोई कार्य किया जाता था। पानी की समस्या का निदान करने के लिए हमने अपने गांव के सथियों के साथ मिलकर गांव के पास 12 हेक्टयर के जंगल में चालखाल और पोखर बनाने का कार्य शुरू किया, हम लोग अभी तक 3000 से 3500 तक चालखाल

और छोटे पोखरों का निर्माण कर चुके हैं।

प्रश्न - आप जो पेड़ लगाते हैं उनके संरक्षण के लिए क्या कार्य करते हैं ?

उत्तर - पेड़ लगाने से ज्यादा लगाए गए पेड़ों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर ऐसा होता है कि चरने वाले जानवर पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे द्वारा 3 हेक्टयर में जो वृक्षारोपण किया गया उसके संरक्षण के लिए हमने उसके चारों तरफ से बांउड्री बना रखी है और हम रोपण की लगातार निगरानी करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे वृक्षों के संरक्षित रहने का एक बड़ा कारण लोगों का इस रोपण के प्रति अपनेपन की भावना है, क्योकि जब कोई कार्य जन सहयोग से किया जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी आम जन भी उठाता है।

प्रश्न - जब आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, तो किस प्रकार समस्याओं से आपका समाना हुआ ?

उत्तर - जब मैने प्रकृति संरक्षण के कार्य करना शुरू किया, तो लोगों ने मुझे पागल कहना प्रारंभ कर दिया था। कई तरह के सवाल लोगों ने मेरे उपर खड़े किए। मुझे नाकारा समझा जाने लगा। क्योंकि मैने इस कार्य के लिए अपने नौकरी छोड़ दी थी। लोगों ने मेरे पिता जी को मेरी शादी नहीं होगी, ऐसे ताना देना शुरू कर दिया था। जिस कारण से मेरे घर वालों का मुझसे भी मन मुटाव हो गया था । पर मैने तो निर्णय ले लिया था कि यह जीवन पर्यावरण को ही समर्पित करना है।

प्रश्न - पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हुए आप अपनी जीविकार्पाजन कैसे करते हैं अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं ?

उत्तर - जब मैने नौकरी छोड़कर प्रकृति संरक्षण के लिए अपने अपको समर्पित किया और अलग-अलग गांव में जाकर पौधारोपण शुरू किया था, तब मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि इस कार्य के लिए संसाधन कहॉ से आएंगे। तब मैने पौधों की कलमें और बीज एकत्रित कर एक नर्सरी का निर्माण किया, जिससे हुआ यह की मुझे रोपण के लिए पौधे भी उपल्ब्ध हुआ और वह बाद में मेरे अजीविका का भी साधन बनी। इसके अलावा हमारी खेती से होने वाली आमदानी भी मेरी जरूरतें पूरी करने का एक स्त्रोत है। इन सब के अलावा गांव में होने वाले विकास कार्यों में ड्राइंग-डिजाइन के साथ काम करके अपनी जीविकार्पाजन कर लेता हूं।

प्रश्न - क्या आपके कार्य से समाज या आगे वाली पीढ़ी पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है ?

उत्तर - जब से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना शुरू किया, तो मैने विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ पौधारोपण शुरू किया था। आज के समय में 400 से भी ज्यादा विद्यालय हमारे साथ जुड़े हुए है। जिनमें हम लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर विचार गोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम चलाते है। इसका असर यह हुआ कि आज हमारे क्षेत्र में जहां कही भी विद्यालयों या छात्र-छात्राओं द्वारा पौधारोपण किया जाता है, तो वे लोग मुझे रोपण के फोटो भेजते है। यहां तक की अब मेरे जन्मदिन पर मेरे नाम से पौधारोपण किया जाने लगा है।

प्रश्न - वर्तमान में आपका परिवार आपके कार्य से संतुष्ट है या नहीं ?

उत्तर - हां, शुरूआत में तो मेरे निर्णय का मुझे मेरे परिवार से कुछ समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। जब उनको मेरे कार्य का महत्व समझ आया, तो उन्होने मेरा सहयोग करना शुरू कर दिया। अब मैं और मेरा परिवार दोनों पर्यावरण के लिए समर्पित हैं।

सक्षात्कार के अंत मे चंदन सिंह जी ने बताया कि जब से मैंने प्रकृति संरक्षण के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया है, तब से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा कोई कार्य अर्थिक तंगी की वजह से रूका हो। मुझे ऐसा लगता है जब आप प्रकृति के कार्य को अपना ध्येय बनाते है, तो आपको अर्थ की नहीं पवित्र मन की जरूरत होती है। □

उत्तर प्रदेश ने की नदी नीति बना

रमन कान्त

(लेखक - नदी पुत्र एवं नीर (NEER) फाउण्डेशन के संस्थापक हैं।)

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां गंगा जैसी बड़ी नदी भी बहती है तो पांवधोई जैसी छोटी नदी भी। गंगा नदी के बहाव की सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश में ही तय करती है। यहां चार प्रकार की नदियों का अस्तित्व मिलता है।

- ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल किसी अन्य राज्य में है और वे उत्तर प्रदेश से होते हुए किसी अन्य राज्य में प्रवेश कर जाती हैं।
- ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल किसी अन्य राज्य में है और वे उत्तर प्रदेश में आकर किसी अन्य नदी में समाहित हो जाती हैं।
- ऐसी नदियां जो कि उत्तर प्रदेश के ही किसी जनपद से प्रारम्भ होती हैं और आगे दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाती हैं।
- ऐसी नदियां जो कि उत्तर प्रदेश के ही किसी जनपद से प्रारम्भ होती हैं और वे उत्तर प्रदेश में ही किसी अन्य नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं।

उपरोक्त चारों प्रकार की नदियों की अपनी अलग-अलग समस्याएं भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से सभी की तीन प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं।

- पानी की कमी।
- अति' मण।
- प्रदूषण।

नदियों की इन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही उत्तर प्रदेश की नदियों के समाधान खोजने का प्रयास समाज व सरकार द्वारा साझे प्रयास से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक-दो या उससे अधिक ऐसे कार्यकर्ता या संगठन मौजूद हैं जोकि अपनी स्थानीय नदियों की चिन्ता करके समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इन कार्यों के बूते कहीं अच्छे परिणाम दिख रहे हैं तो कहीं कठिनाइयां अधिक होने के चलते कार्य परिणामों में नहीं बदल पा रहे हैं। नदी संबंधी सर्वसम्मत ज्ञान का अभाव भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। प्रदूषित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अतिक्रमित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चहिए, पानी की कमी से जूझ रही नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा तीनों समस्याओं ग्रसित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इन सवालों के जवाब न होने के कारण कहीं तकनीकि रूप से गलत कार्य होने की सम्भावना रहती है तो कहीं कार्य से किसी नियम विशेष का उल्लंघन जाने-अनजाने हो जाता है।

वर्तमान में जहां समाज के बहुत कार्यकर्ता अपनी नदियों की चिन्ता कर रहे हैं वहीं सरकार भी अपनी नदियों के प्रति

> **"नदी संबंधी सर्वसम्मत ज्ञान का अभाव भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। प्रदूषित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अतिक्रमित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चहिए, पानी की कमी से जूझ रही नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इन समस्याओं से ग्रसित इन सवालों के जवाब ढूंढ़ने होंगे। समाज के बहुत से कार्यकर्ता एवं सरकार भी नदियों की चिन्ता के प्रति संवेदनशीलता दिखाई दे रही हैं।**

ने की पहल

संवेदनशीलता दिखाती दिख रही है। ऐसे में हमारे पास अपनी नदियों के पुनर्जीवन व रखरखाव हेतु एक सर्वमान्य व उचित समाधान होना ही चाहिए। नदियों के हित में एक सर्वमान्य योजना का होना किसी भी देश-प्रदेश के लिए एक सटीक कदम होगा। नदियों संबंधी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर नीर फाउंडेशन व वाटर एडने उत्तर प्रदेश की एक सामूहिक नदी रखरखाव व पुनर्जीवन की नीति बनाने का प्रयास प्रारम्भ किया है। यह ऐसी नीति होगी जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में नदी पुनर्जीवन का कार्य स्थाई रूप से आगे बढ़ सकेगा। इस विचार को साकार करने हेतु विगत 31 अगस्त, 2022 को नदी समग्र चिन्तन का आयोजन किया गया। इस नदी चिन्तन के 6 मुख्य बिन्दु चर्चा हेतु रखे गए।

- नदियां और प्रदूषण
- नदियां और कृषि
- नदी और जीवीकोपार्जन
- नदियां और जैव-विविधता
- नदियां और कानून
- नदियां और समाज

इस मन्थन को 6 अलग-अलग सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सत्र को एक विषय दिया गया था। उस विषय के कुछ बिन्दु भी तय किए गए थे। उन बिन्दुओं के अतिरिक्त भी प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक सत्र को एक समन्वयक व दो सह-समन्वयकों ने संचालित किया। सत्र में मौजूद सभी महानुभावों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ सुझाव लिखित में भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश की नदी नीति के प्रारूप को विकसित करने की दिशा में यह पहला चरण है। दूसरे चरण में लखनऊ घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर आमजन की भी राय ली जाएगी। इसके लिए यह प्रारूप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को भेजा जाएगा जिससे कि जनपद के सभी नदी कार्यकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों, किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व धार्मिक संगठनों से इस प्रारूप पर उनकी राय ली जा सके। प्रत्येक जनपद से आई हुई राय को भी इस प्रारूप का हिस्सा बनाया जाएगा।

इस चिन्तन में परमार्थ निकेतन के संस्थापक परम पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी, टैक्सएब के संस्थापक डॉ. मनु गौड़, डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. वेंकटेश दत्त, वाटर एड के उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री फर्रूख रहमान खान, योगाचार्य श्री चैज इब्राहिम द्वारा लिया गया। भारतीय कृषक समाज के संस्थापक श्री कृष्णवीर चौधरी, पदमश्री भारतभूषण त्यागी एंव पदमश्री कंवल सिंह चौहान, प्रोफेसर पी.के. सिंह, डॉ. कृपाल दत्त जोशी, कला चौपाल की संस्थापक श्रीमती लीनिका जैकब द्वारा लिया गया। आई.आई.टी. कानपुर के प्रोफेसर डॉ. विनोद तारे, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के निदेशक श्री सुरेश बाबू एंव लापोड़िया गांव राजस्थान में पानी की अलख जगाने वाले श्री लक्षमण सिंह, नीति विश्लेषक श्री गोपालकृष्ण, माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री सावाहिक सिद्दीकी, आई.ए.एस. श्री हीरालाल, नदी कार्यकर्ता श्री उमा शंकर पाण्डेय, श्री नवीन कुमार, श्री संजय विश्नोई, श्री सिदार्थ शर्मा, श्री शुभम कौशिक, श्री अजय सिंह तथा नदी पुनर्जीवन के लिए बनी पहली बॉलिवुड फिल्म के नायक श्री यजुवेन्द्र प्रताप सिंह सहित सरकार के समाज के करीब 100 प्रतिनिधियों ने इस चिन्तन में भाग लिया।

इस चिन्तन से उत्तर प्रदेश का देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जोकि अपनी नदियों की चिन्ता करते हुए उनके स्थाई समाधान की पहल कर रहा है। इस चिन्तन बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश जहां नदियों के

सन्दर्भ में राज्य नदी नीति बनाने की ओर आगे बढ़ा है वहीं एक नदी पुनर्जीवन प्रारूप भी विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। नदी समग्र चिन्तन से सभी सुझावों के साथ एक प्रस्ताव पास करके उसे आगे बढ़ाने की पहल की गई। यह प्रस्ताव लखनऊ घोषणा पत्र के नाम से जारी किया गया। इस लखनऊ घोषण पत्र के सभी सुझावों को राज्य के सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारियों के पास इस आशय के साथ भेजा गया है कि जिलाधिकारी अपने जनपद के सभी नदी कार्यकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों, किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व धार्मिक संगठनों से इस प्रारूप पर उनकी राय ले सकें। प्रत्येक जनपद से आई हुई राय को भी इस प्रारूप का हिस्सा बनाया जाएगा। इस प्रारूप को उत्तर प्रदेश व देश में नदियों के लिए कार्य करने वाले अन्य लोगों व नीति विशेषज्ञों के पास भी भेजकर उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में पूज्य स्वामी चिदानन्द जी के संरक्षण व जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में एक 19 सदस्य कमेटी का भी गठन किया गया है। सभी के सुझाव आने के बाद बनारस में यह कमेटी बैठकर उत्तर प्रदेश की नदी नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी। इसके पश्चात यह प्रारूप कानून बनाने के लिए राज्य के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंप दिया जाएगा। □

लखनऊ घोषणापत्र के मुख्य बिन्दु

1. भारत के समाज द्वारा सदियों से हमारी नदियों को पूर्णतः नैसर्गिक जीवंत एवं पोषक प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आवश्यकता है कि प्रत्येक नदी प्रणाली को एक 'प्राकृतिक व्यक्ति' का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।
2. प्रदेश में नदी भूमि क्षेत्र को नदी संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया जाए। उद्गम/प्रदेश में प्रवेश बिन्दु से लेकर नदी के अन्तिम छोर तक नदी क्षेत्र अधिसूचित किया जाए।
3. नदी में किसी भी तरह का शोधित व गैर-शोधित अवजल व ठोस अपशिष्ट न डाला जाए।
4. नदियों के प्रवाह की आजादी सुनिश्चित करने हेतु नदी की जमीन नदी की ही रहनी चाहिए।
5. नदी नीति के क्रियान्वयन हेतु राज और समाज को आगे रखते हुए ऐसी समन्वित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें दोनों की भूमिकाएं स्पष्ट परिभाषित हों।
6. नदी का जल और भूजल एक दूसरे के पूरक होते हैं इसीलिए भूजल को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय समाज के साथ वोरिंग की गहराई सुनिश्चित होनी चाहिए।
7. नदी पर बांध और तटबंध पर प्रतिबंधित होना चाहिए।
8. नदियों की भू-सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए भू-आकृतिकी से छेड़-छाड़ नहीं की जानी चाहिए।
9. चूंकि नदी प्रबंधन में समाज जिम्मेदार भूमिका भी अपेक्षित है अतः नदी से संबंधित सभी आंकड़े, योजनाओं तथा परियोजनाओं से संबंधित सूचना समुचित माध्यमों के जरिए संबंधित जन को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10. नदी प्रबंधन करते समय परंपरागत भारतीय ज्ञान तंत्र तथा स्थानीय कौशल व तकनीक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
11. बाढ को नहीं बाढ के विनास को रोकने का प्रयास करना चाहिए।
12. नदी नीति के क्रियान्वयन हेतु राज और समाज को सामने रखते हुए समन्वित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें राज और समाज की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। नदी और समाज के बीच सतत एवं मजबूत आपसी सम्पर्क व संवाद को स्थापित किया जाना चाहिए।
13. नदी की जैव-विविधता को प्राथमिकता देनी चाहिए न कि उपयोगिता को।
14. प्रत्येक नदी का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाए।

असल काम यही है हम अपनी जड़ों से ना उखड़ जाएं और लौटने का ही नहीं बल्कि पूरे तालमेल के साथ कुदरत को सहेजने के तमाम रास्तों की मरम्मत भी करते जाएं। जीवन और आजीविका की धुरी तो पानी ही रहेगा, इसलिए ऐसे कामों की बात पुरज़ोर होनी चाहिए ताकि ऐसे काम एक राज्य में नहीं बल्कि उन तमाम जगह दिखाई देने लगें जहां खेती पर आश्रित आबादी बसी है। साल 2015 में किसानों की खुदकुशी के मामलों की कचोट ने नाना पाटेकर को खेती की दुश्वारियों की तह में जाने का मौका दिया। तकलीफ से घिरे परिवारों को करीब से समझा और इस तरह नदी-तालाब-बावड़ियों को संभालने और आजीविका का रास्ता बनाने का जो काम 'नाम' संस्था के ज़रिए मराठवाड़ा के 40-50 गांवों से शुरू हुआ था वो आज 400 के पार जा पहुँचा है

छोटी नदियों के लिए 'नाम' के बड़े काम

डॉ. क्षिप्रा माथुर

(लेखिक - दो दशक से पत्रकारिता और पत्रकारिता से जुड़ी, पत्रकारिता में कैंपेन एडिटर, अमेरिका के ग्लोबल स्ट्रेट व्यू अखबार की कंसल्टिंग एडिटर हैं।)

किसानों और आदिवासियों ने धरती को हमेशा धानी और हरियाली चुनरी से संवारा है। लेकिन कारखानों और इमारतों की तीमारदारी में लगी दुनिया का नदियों की मिट्टी, समंदर की रेत, पहाड़ के पत्थर और पेड़ों की लकड़ियों से लगाव छूटने से पूरी सभ्यता का एक मुहाना टूटने लगा है। ज़मीन, पत्थर, मिट्टी सब जितनी तेज़ी से खिसक रहे हैं, उतनी तेज़ी से उन्हें पनपने देने का वक्त हमारे पास बचा भी नहीं है। जमीन से खींचकर पानी निकालने की योजनाओं ने इतना पानी निकाल लिया कि अब कई इलाकों की प्यास बुझाने को पानी भी उधार लेना और खरीदना पड़ रहा है। एक राज्य को दूसरे से, एक शहर को अगले से और एक गांव को बगल से, नहरों से। दूसरी तरफ कई इलाके असल किल्लत नहीं होते हुए भी इसलिए भुगत रहे हैं कि उन्होंने पानी के बांधने के पारम्परिक तरीकों की कद्र नहीं की और आज ही के दौर में मुहैया समाधान भी उन तक पहुंचने में नाकाम रहे।

समुदाय की साझेदारी

फसलों की प्यास बुझाने में जमीन के भीतर का करीब 60 फीसद पानी इस्तेमाल होता है। दुनिया की 16 फीसद आबादी और केवल चार फीसद पानी की हिस्सेदारी वाले देश में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को पानी लाने ले जाने के लिए औसतन ढाई किलोमीटर दूर जाना होता है। सरकारी आंकड़े ही देखें तो देश के करीब आधे ज़िलों के गहरे तले भी सूख चुके हैं। तरसती उम्मीद के बीच मानसून बरसता भी है लेकिन ना उसे सहेजने वाले तालाब-बावड़ियों की अंजुरी अपनी पूरी नाप में होती है ना ही सड़कों की बनावट ऐसी कि बहता पानी जमा होकर कीचड़ करने की बजाय जमीन में पैर जाए। जहां नदी, ताल, बावड़ियां हैं वहां उनकी देखरेख की योजनाएं अगर बनती भी हैं तो कागजों में ही बहती रह जाती हैं। गांवों तक सड़कें बिछाकर और पूरे देश को हाईवे से जोड़कर हमने सफर तो आसान कर लिया है मगर कच्ची ज़मीनों की सांसें रोककर पानी के पैरने का रास्ता भी रोक दिया है। जल-आन्दोलन की कड़ियों के आलेखों में इसके तकनीकी समाधान की भी बात की है। आज समुदाय, संस्थाएं, सरकार और अकादमिक दुनिया की साझेदारी के गिने चुने नमूने ही नज़र में हैं हमारे पास। इनमें से एक कारगर काम हुआ है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में नाना पाटेकर और मकरन्द अनासपुरे की अगुवाई में काम कर रही संस्था 'नाम' के ज़रिए।

चार सौ गांव भरेपूरे

पर्दे के अभिनय के रोमांच से बाहर असल जीवन में लोगों के लिए ठोस काम करना आसान रास्ता नहीं होता। नाना पाटेकर ने जीवन में कड़ा संघर्ष किया और अपनी कशमकश को पर्दे पर उतारने के साथ ही जीवन के एक पड़ाव पर आकर समाज की सजल संवेदनाओं के साथ जुड़ना भी तय किया। साल 2015 में किसानों की खुदकुशी के मामलों की कचोट ने उन्हें खेती की दुश्वारियों की तह में जाने का मौका दिया। लोगों के बीच काम करने के अनुभव साझा करते हुए वे कहते हैं कि गांव में खेती बाड़ी और कुदरत की देखरेख करने में सब माहिर हैं, उन्हें कोई बाहर से आकर क्या सिखा सकता है। तकलीफ से घिरे परिवारों को करीब से समझा तो जाना कि यदि पानी का प्रबन्ध ठीक हो जाए तो खेती के संकट से खुद निपटने में वे लोग सक्षम हैं। और इस तरह नदी-तालाब-बावड़ियों को संभालने का काम मराठवाड़ा के 40-50 गांवों से शुरू हुआ। समुदाय की समझ, जल के असल जानकारों, और पहले से मौजूद जल-प्रबन्धन के कारगर मॉडल की जानकारी जुटाकर गांव वालों की भागीदारी से तालाबों की खुदाई, मरम्मत, पानी के कुदरती रास्तों की रुकावटें हटाने के तमाम काम किए। आखिरकार तो गांववासियों को ही तय करना होता है कि उनके यहां किस काम की प्राथमिकता है, फिर वही योजना बनाते हैं और 'नाम' के जरिए खुदाई की मशीनों का इन्तजाम हो जाता है। इस तरह बड़े पैमाने पर सबके जुटने से बारिश के मौसम में पानी की भरपूर आवक को साफ और दुरुस्त हुए नदी-नाले सहेज लेते हैं। आज ये काम 350 गांवों में फैला है तो सरकारी महकमे और कारपोरेट जगत दोनों के जुड़ने से कोविड महामारी के बावजूद कहीं काम नहीं रुका।

अपनी मिट्टी में जमे पांव

पानी का काम लगातार जारी रहने से उन इलाकों में उम्मीद तो बंधी ही, खुदकुशी की बजाय लोग जीवन को चुनने लगे। 'नाम' के कामकाज संभाल रहे गणेश थोराट से जब तब्दीलियों के बारे में जाना तो लगा कि एक-एक परिवार का संभलना, खेती की ओर

लौटना, युवाओं की रूचि फिर से खेती की तरफ होना, साल में तीन उपज ले पाना, डेयरी और दूध उत्पादन बढ़ना ये छोटी तब्दीलियां नहीं हैं। और सबसे अहम बात ये कि अब रोज़गार की तलाश में पानी से आबाद गांवों से कोई घर बार छोड़कर पलायन नहीं करता। घर का छूटना जीवन भर की दुखती रग होती है। साल 2016से 2019 के बीच का राज्य का आंकड़ा भी ज़ाहिर कर रहा है कि जिन इलाकों में पानी की कलकल सुनाई देने लगी है वहां अब जीवन की हलचल है। हालांकि कोविड महामारी के दौरान करोड़ों किसान और श्रमिकों की हिम्मत टूटी तो नाना पाटेकर ने अपने सोशल पेज के ज़रिए लोगों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोष में धन जमा कराने और इस मुश्किल दौर में सरकार का साथ देने की

अपील भी की। असल काम यही है हम अपनी जड़ों से ना उखड़ जाएं और लौटने का ही नहीं बल्कि पूरे तालमेल के साथ कुदरत को सहेजने के तमाम रास्तों की मरम्मत भी करते जाएं। जीवन और आजीविका की धुरी तो पानी ही रहेगा, इसलिए ऐसे कामों की बात पुरज़ोर होनी चाहिए ताकि देश में ऐसे काम एक राज्य में नहीं बल्कि उन तमाम जगह दिखाई देने लगें जहां खेती पर आश्रित आबादी बसी है।

ओढा जीवंत और समरस

महाराष्ट्र की करीब चार सौ छोटी नदियां जिसे मराठी में 'ओढा' कहते हैं उनका जीवन लौट आया है। ये धरती का ऋण है जो 'नाम' संस्था की पूरी टीम ने मिलकर चुकाया है। कहीं सफाई हुई, कहीं मुहानों की मरम्मत, कहीं बांध बने तो कहीं तल में जमी मिट्टी और गन्दगी को हटाने का काम हुआ। समुदाय का भरोसा, उनका श्रम और उनकी भागीदारी ने जो तस्वीर इस प्रदेश के कैनवास पर उतारी है उससे पानी को तरस रहे और राज्य को अपने यहां के रंग भरकर नए कैनवास तैयार करना आसान हो सकता है। परनेर के जामगांव, रत्नागिरी की साखरपा, बीड के पांढरी और टाकरवन, देवडे की उमरद, रत्नागिरी के संगमेश्वर, सतारा का कलेढोण, गारळेवाडी, मालवण के नांदरूख, जामखेड के पिंपळगांव, विंचरणा और फ ाबाद, धुळे के रानमळा, चाळीसगांव कुंर, कुंजर, बोढरे, पारनेर के वडगांव आमली, आंधळी का विट्ठल गंगा प्रोजेक्ट, जालना का भराडखेडा, अहमदनगर का जामगांव और पारनेर, कोल्हापुर का सावंतवाडी, बटकनंगले, सोलापुर का माळशीरस, जालना का धनसावंगी, झुरखेडा, जळगांव जैसे सैंकड़ों नदी-नाले हैं जिन्होंने बारिश से आए और ज़मीन में जमा पानी की संभाल के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है। आजीविका की आस भी साथ साथ जगाने वाली इस मुहिम से जुड़ने के लिए महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई इलाकों से लोग आने लगे हैं। पानी के ऐसे काम यदि देश के हर उस इलाके में होने लगे जहां कुदरत की मनमानियों का असर खेती-किसानी पर सबसे ज्यादा आता है तो सिर्फ जलवायु के संकट से ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक मजबूती के निशां भी दिखाई देने लगें।

बड़े पैमाने, नए ठिकाने

नाना पाटेकर इस काम का श्रेय उस पूरी टीम को देते हैं जो बिना थके, दिन रात की परवाह किए बगैर इस काम में जुटे हैं। आज बीड इलाके की रिद्धी-सिद्धी नदी और सोलापुर के माड़ा तालुक की बींद ओढा 34 किलोमीटर तक फैलकर अपने पूरी तरंग में है। मगर सिर्फ असल हासिल तब है जब बदलाव पर लगातार नज़र रखकर हर काम को वैज्ञानिक मानकों पर जांचे-परखे जाने के बाद उन्हें दोहराया भी जा सके। इसके लिए साढ़े तीन सौ गांवों में हुए पानी के काम पर तीन साल तक 'नाम' की पैनी नज़र रहती है। जिसमें पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक हर पैमाने का पानी से ताल्लुक को दर्ज किया जाता है। इन तजुर्बों को अपनी भाषा, अपनी लोक समझ और लोक-मन के साथ दुनिया से साझा करने की जितनी दरकार है उतनी ही इस बात की भी कि शोधार्थी और अकादमिक जगत इन कामों के दस्तावेज़ तैयार करें और पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं।

विश्व गुरू की परिकल्पना को साकार होता देखने की चाह वाली नई शिक्षा नीति देशज ज्ञान और हुनर से नई पीढ़ी को जोड़ने के हक में है। लेकिन गुरू बनकर सिखाने और बेहतर साबित करने के गुरूर की बजाय नदियों ने सखा भाव के साथ ही बहना जाना है। 'नाम' की टीम इसी भाव के साथ पूरे भारत को ही अपना दायरा मानकर चल रही हैं। इसलिए देश के दूसरे हिस्सों से जल-स्रोतों को जीवित करने में रुचि दिखाने वाले और जानकारी चाहने वाले लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है।

पानी के बेहतरीन कामों के दोहराव के मानस के साथ देश को जल-संकट से निजात मिले ये हम सबकी साझी जीत होगी। जीवित होती, फिर से सांस लेती नदियां हमारी पाठशालाएं बनें, अपनी कहानियां कहें और संस्कृति के बहाव को आने वाली पीढ़ी तक लेकर चलें तो हम पानी के इर्द गिर्द फिर नई शक्ल लेती इन्सानी बसावट की बारीकियां भी समझ पाएं। नदियों को लेकर साहित्य लेखन के लिए भी जन-साधारण को तैयार करना होगा जिनके पास अपने गीत हैं, अपनी बोलियां, अपनी कला और अपनी खास गढ़ाई है जो पानी को अपने तरीके से पिरोने और पेश करने की काबिलियत रखती हैं। तलाश छूट जाए सिर्फ ये बहाव बचा रहे, तो ही संस्कृति की थिरकन महसूस होगी। □

पर्यावरण प्रहरी

डॉ. सुनीश बक्शी

(लेखक - आई.एफ.एस. अधिकारी, महानिरीक्षक, वन विभाग, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं।)

11 सितंबर 1730 को खजराली (राजस्थान) में बिश्नोई जनजाति के 360 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसका कारण यह था कि उन्होंने मारवाड़ के राजा द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को काटे जाने पर आपति जताई थी।

भारत ने वन संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से बाघ, शेर और हाथियों के संरक्षण में अभूतपूर्व उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वन क्षेत्र के कर्मचारियों की समर्पित टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राष्ट्र के पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए समर्पित है। इन संरक्षण सफलताओं को प्राप्त करने के पीछे मुख्य बल राज्य वन विभागों के प्रतिबद्ध फील्ड स्टाफ है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर, अक्सर अपने परिवारों के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं के आराम से दूर, वे समर्पित रूप से सरकार की नीतियों को निष्पादित करते हैं और राष्ट्र की पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में योगदान देते हैं। वे न केवल हमारे राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों को अतिक्रमणकारियों, इमारती लकड़ी तस्करों, खनन माफियाओं और संगठित शिकारियों से बचाते हैं बल्कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, असहाय ग्रामीणों और जंगली जानवरों के बीच रक्षा की अटूट दीवार के रूप में खड़े होते हैं।

वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में वनकर्मियों द्वारा किए गए अनुकरणीय शौर्य और बलिदानों को मान्यता देते हुए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस घोषित किया है। हम इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

11 सितंबर 1730 को खजराली (राजस्थान) में बिश्नोई जनजाति के 360 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसका कारण यह था कि उन्होंने मारवाड़ के राजा द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को काटे जाने पर आपत्ति जताई थी। सैनिकों को मारवाड़ के महाराजा, अभय सिंह ने खजराली गांव में पेड़ काटने के लिए भेजा था ताकि नए महल के लिए लकड़ी उपलब्ध हो सके। यह हत्याएं उनके मंत्री गिरिधर भंडारी के आदेश पर की गई थीं। पेड़ों के लिए यह बलिदान अमृता देवी बिश्नोई के शब्दों में अच्छी तरह से कहा गया है- ''सर सांथे रूख राहे, तो भी सस्ती जान।'' यही संकल्प उनकी तीन बेटियों और 300 से ज्यादा बिश्नोई महिलाओं ने दिया था। अमृता ने कहा कि खेजड़ी के पेड़ बिश्नोई के लिए पवित्र थे, और उनके विश्वास ने उन्हें पेड़ों को काटने की अनुमति देने से मना कर दिया। इसी महान बलिदान के कारण राजा ने पेड़ों की कटाई के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया। बिश्नोई के निष्क्रिय प्रतिरोध से स्तब्ध अभय सिंह ने अपने आदमियों को वापस बुलायाऔर व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्री के कार्यों के लिए माफी मांगने के लिए गांव की यात्रा की। उसने फरमान सुनाया कि गांव में फिर कभी राज्य के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मूल रूप से जेहनाद नामक इस गांव का नाम बाद में खजराली कर दिया गया और इस नरसंहार का स्थल बिश्नोई आस्था के लिए तीर्थ स्थल बन गया। इस प्रयास का पर्यावरणीय वकालत पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, और बाद में नरसंहार 20वीं शताब्दी चिपको आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाने लगा।

हर साल कई 'हरित सैनिक' कर्तव्य की रेखा में सर्वोच्च बलिदान करते हैं, जबकि कई अन्य जीवन के लिए अक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार उनके परिवार के सदस्यों के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। प्रकृति के इन रक्षकों को सुरक्षित कार्य करने की स्थिति प्रदान करने के साथ-साथ इन हरित सैनिकों, जो हमारे भविष्य के लिए अपने वर्तमान का त्याग कर रहे हैं, को बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय नीति बनाई जा रहे हैं। देश भर में कम से कम 50,000 फील्ड फॉरेस्टरों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होने की संभावना है और यह उन्हें राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उत्साहपूर्वक काम करने के लिए प्रेरित करेगा। □

औषधीय पौधों पर प्रशिक्षण कार्यशाला

नर्मदा समग्र न्यास द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI) परिसर, कलियासोत डैम के समीप, भोपाल में दिनांक 2-4 सितम्बर में **''औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं औषधीय पौधों की गृह वाटिका तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण''** कार्यशाला का आयोजन किया गया।

तीन दिवसीय कार्यशाला में औषधीय पौधों की पहचान, उनके बारे में प्रमुख जानकारियाँ, उपयोग, उनके उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, धार्मिक-आध्यात्मिक, पारंपरिक प्रथाएं, सामाजिक, आर्थिक, व्यावहारिक एवं व्यावसायिक विषय बिंदुओं को समाहित करते हुए सत्र आयोजित हुए। जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा न केवल अपना प्रस्तुतीकरण दिया, अपितु अपने अनुभव साझा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा की एवं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। यह कार्यशाला केवल चर्चात्मक न होकर व्यावहारिक दृष्टिकोण को एवं प्रत्यक्ष रूप में कार्य कैसे हो रहे हैं इसको देखने समझने दृष्टि से प्रतिभागियों को अहमदपुर नर्सरी में एवं वाल्मी परिसर (जैव विविधता पार्क एवं जल संरक्षण संरचनाएँ) का भ्रमण कराया गया, साथ ही MFP बरखेड़ा पठानी स्थित प्रसंस्करण इकाई का दौरा भी कराया गया।

कार्यशाला में निम्नलिखित विषय एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया गया।

- जल और पौधों का सह-संबंध (जल संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन) श्री विवेक भट्ट, जल विशेषज्ञ एवं सह-प्राध्यापक, (कोर्स संचालक) जल संसाधन प्रबंध एवं अभियांत्रिकी, वाल्मी;
- औषधीय पौधे एवं जैव विविधता श्री विवेक पांडे, तकनीकी विशेषज्ञ, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, म.प्र. जैव विविधता बोर्ड;
- म.प्र. के औषधीय पौधे डॉ. गुरपाल सिंह जस्याल, वन औषधी विशेषज्ञ;
- औषधीय पौधों का व्यवसायिक उत्पादन श्री अजय पाटीदार, कृषि विशेषज्ञ, मिसरोद;
- अपने आसपास औषधीय पौधों की पहचान एवं प्राथमिक उपचार में प्रयोग। साथ ही इस क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों/सामाजिक संस्थाओं की भूमिका, औषधियों के आयात-निर्यात संबंधित मुख्य बातें डॉ. तृप्ति सिंह, अध्यक्ष, वृंदा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्र सलाहकार;
- दैनिक जीवन में औषधीय पौधों का उपयोग एवं संबंधित परंपरा श्री प्रदीप त्रिपाठी, प्राकृतिक चिकित्सा/आयुर्वेदाचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महासचिव, रेडक्रास म.प्र.;
- डॉ. सुदेश वाघमारे जी सम्पूर्ण कार्यशाला में प्रोग्राम मेंटॉर की भूमिका में रहे, आपके द्वारा औषधीय पौधों का प्राथमिक परिचय और प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया। समय-समय पर आपका मार्गदर्शन प्रतिभागियों को मिलता रहा।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन CRISP के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक श्री श्रीकांत पाटिल द्वारा किया गया। कार्यशाला में सम्मिलित हुए प्रतिभागियों के साथ एक खुला सत्र भी आयोजित हुआ जिसमें जिज्ञासा समाधान के अलावा अपने अनुभवों एवं इस प्रकार के कार्यों में आने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई।

साथ ही प्रतिभागियों का क्षमता विकास परीक्षण भी हुआ जिसके उपरांत कुछ को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम का समापन, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा किया गया। कार्यशाला के अंतिम दिवस प्रतिभागियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्मार्ट सिटी पार्क, भोपाल में पौधारोपण करने का अवसर प्राप्त हुआ। □

प्रतिभागी कौन

- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थीगण;
- वन सुरक्षा समितियों के सदस्य;
- जैव विविधता समितियों के सदस्य;
- ग्राम विकास समितियों के सदस्य;
- अशासकीय संस्थाओं के सदस्य;
- स्व सहायता समूह की महिला सदस्य;
- जल संरक्षण समितियों के सदस्य;
- स्थानीय पंजीकृत वैद्य/प्राकृतिक चिकित्सक एवं औषधि उत्पादक;
- ग्राम पंचायत तथा स्थानीय प्रशासन के सरपंच/नगरपालिका अध्यक्ष/पंच/पार्षद;

प्रतिभागी कहाँ से -

इसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से लगभग 31 प्रशिक्षणार्थी आए हैं (ज्यादातर नर्मदा जलग्रहण से हैं)।

नर्मदा समग्र न्यास द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
" औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं ग्राम वाटिका तैयार करने का प्रशिक्षण "
2-4 सितंबर 2022, भोपाल

नर्मदा समग्र न्यास द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
" औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं ग्राम वाटिका तैयार करने का प्रशिक्षण "
भोपाल

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

रेनबो रेसीडेन्सी योजना के निर्माणाधीन परिसर स्नेहलतागंज इन्दौर में व्यावसायिक संपत्ति का ई ऑफर के द्वारा विक्रय

आवेदन फार्म रु.1180/-

रेरा पंजीयन क्रमांक
P-IND-17-243

कीमत 18.81 लाख से प्रारंभ

निर्माण पूर्णता पर

उपलब्ध सम्पत्ति का विवरण

01	भूतल पर निर्मित कुल दुकान क्रमांक 1 से 32 मे से कुल 10 दुकाने उपलब्ध (क्रं. 08 से 11, 14 से 17, 19 एवं 20)
02	प्रथम तल पर दुकाने क्रमांक 01 से 33 मे से कुल 23 दुकाने उपलब्ध (क्रं. 03 से 06, 08 से 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31 एवं 32)
03	द्वितीय तल पर 3 व्यावसायिक कक्ष (क्रं. 01, 02 तथा 03) तथा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल प्रत्येक तल पर व्यावसायिक कक्ष क्रं. 01 से 06 तक (कुल 21 कक्ष)

नियम एवं शर्तें

- अपसेट मूल्य एवं धरोहर राशि का अवलोकन आनलाईन ब्रोशर में किया जा सकता है।
- समस्त अस्वीकृत प्रस्तावों की धरोहर राशि 45 दिनो मे बिना कटौत्री एवं बिना ब्याज के आवेदन मे अंकित बैंक अकाउन्ट मे लौटाई जावेगी। आवेदन फार्म की राशि वापसी योग्य नही है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन निरस्तीकरण पर 50 प्रतिशत धरोहर राशि राजसात कर शेष राशि वापस की जावेगी।
- स्वीकृत ऑफर मूल्य के अतिरिक्त भूमि डायवर्जन शुल्क, लीज रेन्ट, 12% GST, रखरखाव शुल्क (कार्पस फण्ड), अन्य व्यय, दस्तावेज शुल्क तथा शासन को देय अन्य प्रभार आदि पृथक से देय होगें।
- मण्डल तथा शासन के नियम एवं योजना के ब्रोशर में लिखी शर्तें लागु।
- आवेदन एवं धरोहर राशि आनलाईन/आर टी जी एस (RTGS) से जमा होगी। ऑफर आई.डी. रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त होगा।

संपर्क सूत्र

सम्पत्ति अधिकारी
संभाग क्रमांक :-1, शापिंग काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर,
साइट :- मेन रोड स्नेहलतागंज, इंदौर
फोन : 0731-2554888, 9406912054, 9425328221

योजना की विस्तृत जानकारी एवं आनलाईन बुकिंग की सुविधा www.mphousing.in एवं www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

अन्य गतिविधियाँ...

वरहनगर (बड़ा बड़वा) जिला धार, टीम द्वारा अपने ग्राम के बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करने और शिक्षा के साथ संस्कार हेतु निःशुल्क माँ नर्मदा गुरुकुल का आरम्भ किया है। इस अभिनव प्रयास के लिए नर्मदा समग्र की ओर से शुभकामनाएँ।

31 जुलाई 2022 को नर्मदा समग्र द्वारा होमगार्ड के साथ मण्डला जिले में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। होमगार्ड जिला प्रभारी अधिकारी श्री हेमराज परस्ते जी ने कार्यकर्ताओं को आपदा/दुर्घटनाओं के समय प्राथमिक उपचार एवं DRR के तरीकों से अवगत कराया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में 10 घाटों से कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे।

अर्जुन, कोहा

वानस्पतिक नाम - Terminalia arjuna

फैमिली - COMBRETACEAE

डॉ. सुदेश वाघमारे

सामान्य विवरण

नर्मदा के किनारे जल धाराओं के निकट पाया जाने वाला विशाल वृक्ष है। यह धीरे-धीरे बढ़ता है और जल व कीचड़ में अपनी पकड़ मजबूत बनाये रखने के लिए तने के नीचे रूट-बटरेस बनाता है जो इसे पानी के तेज बहाव के विरूद्ध मजबूती प्रदान करते हैं। इसकी विशाल शाखायें एवं पत्र समूह नीचे की ओर लटकते हैं। यह 100 फीट ऊंचाई तक अनुकूल परिस्थितियों में पाया जाता है।

पत्तियां - लम्बी एवं शंक्वाकर पत्तियां होती है जो ऊपर की ओर हरी तथा नीचे की ओर भूरी होती हैं।

छाल - चिकनी एवं राख से मिलते जुलते रंग की। पुराने वृक्षों से प्रतिवर्ष छाल पपड़ियों के रूप में निकलती रहती है जिसके नीचे तने का हरा रंग दिखाई देता है।

पुष्प - हल्के पीले रंग के पुष्प पाये जाते हैं जो ग्रीष्म ऋतु मार्च से अप्रैल के मध्य आते हैं। पुष्पन के समय मधुमक्खियों के झुण्ड देखे जा सकते हैं जो इनका मधु संग्रहित करते हैं। इनके शहद में अर्जुन पुष्पों की सुगंध आती है जिसे विशेष आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है।

फल - इसके फल लगभग 5 सेमी लम्बे एवं काष्ठीय होते हैं। फलों में पाँच पंख के समान रचनायें पाई जाती हैं, जो इसे जल में डूबने से बचाती है। फल वर्षा ऋतु में और उसके पश्चात सितम्बर से नवम्बर में आते हैं।

सक्रिय रसायन - ट्राइटरपिनॉइड, फ्लेवोनाइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, धातु एवं सूक्ष्म तत्व - एल्युमीनियम, जिंक, कॉपर आदि।

औषधीय उपयोग - हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फेंफड़ों के रोग।

यह भारतीय उपमहाद्वीप का देशज प्रजाति का प्रमुख वृक्ष हैं जिसके विशालकाय वृक्ष मध्य भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य में जलधाराओं के दोनों ओर पाये जाते हैं। जल प्रेमी यह वृक्ष नर्मदांचल में बहुतायत में पाये जाते हैं। एक विशेष प्रकार के 'मोथ' द्वारा इसकी पत्तियां खाकर एक विशेष प्रकार का सिल्क बनाया जाता है जिसे 'टसर सिल्क' कहते हैं। इसीलिए सेरीकल्चर विभाग द्वारा इसका व्यापारिक उपयोग किया जाता है। हालांकि नई दिल्ली के लुटियंस इलाके में इसका पथ-वृक्षारोपण के रूप में बढ़िया उपयोग किया गया है।

ऐसी जनश्रुति है कि जब पांडवों ने अज्ञातवास बिताया तो उसमें एक बंधन यह था कि कोई उन्हें पहचान न पाये। तब अर्जुन ने अपने शस्त्र इस वृक्ष की कोटर में छिपा दिये थे और अज्ञातवास पूरा होने पर वापस प्राप्त कर लिये। शमी के वृक्ष को भी इस जनश्रुति से जोड़ा जाता है; परन्तु शमी का तना इतना विशाल नहीं होता कि उसमें शस्त्र छिपाये जा सकें। अतएव अर्जुन को ही वह वृक्ष मानना चाहिए। नर्मदा समग्र के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध चिन्तक स्व. श्री अमृतलाल वेगड़ ने नर्मदा परिक्रमा की अपनी पुस्तक में आंवली घाट पर अर्जुन के वृक्षों के विशाल रूप की उपमा 'भीमकाय अर्जुन' वृक्षों से की है। इसके पौधे जलीय पारिस्थितकी तंत्र (water ecosystem) का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। निर्विवाद रूप से अर्जुन के पेड़ जल धाराओं के किनारे ही पाये जाते हैं; क्योंकि इसके बीज को अंकुरित होने के लिए पानी-कीचड़ और पर्याप्त गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है।

इसकी छाल के सत्व में पाये जाने वाले रसायन हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप के उपचार में काम आते हैं। 'अर्जुन चाय' भी स्वादिष्ट हर्बल पेय हैं। 'अर्जुनारिष्ट' नाम से भी इसकी छाल के सत्व का उपयोग होता है। जल धाराओं का संरक्षण होने पर ही इस वृक्ष का संरक्षण संभव है।

नर्मदा की चट्टानें

नर्मदा क्षेत्र दो भू-गर्भीय हिस्सों में बंटा हुआ है। इसका उत्तर क्षेत्र नर्मदा एल्युवियम्स पैलीस्टोशियन काल का है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र की सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ ऑर्चीयन्स काल की हैं जो नाइसिक ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। सेडीमेन्ट्री रॉक्स मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, मडरॉक और कार्बोनेट की चट्टानें हैं। फिलाइट्स राक्स मुख्य रूप से बैतूल के उत्तर-पश्चिम भाग में दिखाई देती है। बाग जीराबाद क्षेत्र में भरपूर लाइम स्टोन है। भू-वैज्ञानिकों की दृष्टि से ये चट्टानें 60 से 250 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। अमरकंटक का क्षेत्र डेक्कन ट्रेप के ज्वालामुखी चट्टानों से ढंका हुआ है। अमरकंटक से ग्वारीघाट तक ज्वालामुखी के लावों से बनी काली कठोर चट्टानें हैं। इन चट्टानों को 'महाकौशल शैल' या 'लम्हेटा शैल' नाम से जाना जाता है।

साभार - नर्मदा समग्र (Rafting Through a Civilization : A Travel Logue)

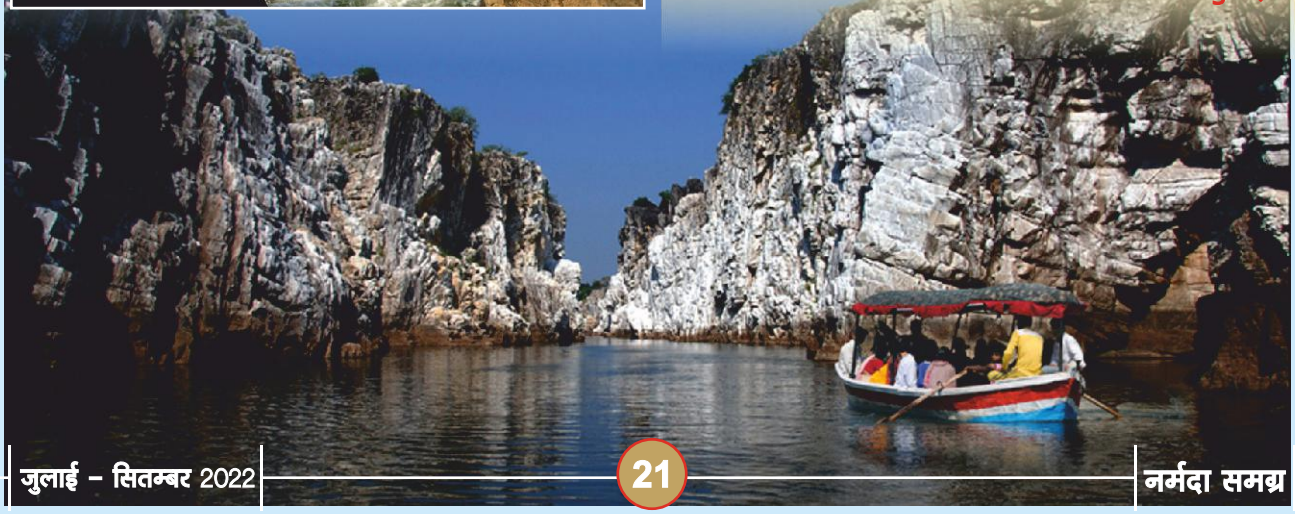

मध्यप्रदेश के रामसर स्थल

दीपक सिंह बैस

(लेखक - नर्मदा समग्र मीडिया समन्वयक)

भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई हैं। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में चार (4), ओडिशा में तीन (3), जम्मू और कश्मीर में दो (2) और मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में एक (1) शामिल हैं। इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत एक है। भारत ने 1 फरवरी, 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। 1982 से 2013 के दौरान, रामसर स्थलों की सूची में कुल 26 स्थलों को जोड़ा गया, हालांकि, इस दौरान 2014 से 2022 तक, देश ने रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमि जोड़ी हैं। इस वर्ष (2022) के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर प्रमाण पत्र में अंकित स्थल की तिथि के आधार पर इस वर्ष (2022) के लिए 19 स्थल और पिछले वर्ष (2021) के लिए 14 स्थल हैं।

मध्यप्रदेश के लिए साल 2022 पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दरअसल एक महीने में मध्यप्रदेश को तीसरी रामसर साइट की उपलब्धि प्राप्त हुई है। इंदौर के यशवंत सागर को रामसर साइट की मान्यता मिलने के बाद मध्य प्रदेश के नाम रामसर साइट में चार उपलब्धि दर्ज कर ली गई है। इससे पहले 26 जुलाई 2022 को साख्य सागर 03 अगस्त, 2022 सिरपुर तालाब को मध्य प्रदेश में एक और आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया था। वही बाद में इंदौर के यशवंत सागर को भी इस सूची में जगह दी गई है मामले में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सूची जारी कर इसकी घोषणा की है। इसी के साथ यह इंदौर का दूसरा और प्रदेश का चैथा तालाब हो गया है, जिसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है।

यशवंत सागर 2000 एकड़ में फैला हुआ है। गंभीर नदी के पानी को रोककर इसके लिए बांध बनाया गया। होलकर महाराज तुकोजीराव तृतीय ने इंदौर के पश्चिमी हिस्से में जलापूर्ति के लिए द्वारा इसे वर्ष 1900 बनवाया था। इसका नामकरण उन्होंने अपने बेटे यशवंतराव द्वितीय के नाम पर किया था। जिसके कारण यशवंत सागर का निर्माण हुआ था। 1992 में ही से प्रमुख पक्षी का क्षेत्र घोषित किया गया था। यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है और साथ ही मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। वर्तमान में इसका उपयोग मुख्य रूप से इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। यशवंत सागर जलाशय इंदौर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक का खिताब हासिल करने वाले इंदौर को अक्सर मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इस आर्द्रभूमि का जलग्रहण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि है। यशवंत सागर को मध्य भारत में दुर्लभ सारस क्रेन का गढ़ माना जाता है। झील के बैकवाटर में बहुत सारे उथले क्षेत्र हैं, जो कि वैडर्स और अन्य जलपक्षी के लिए अनुकूल हैं। जैसे ही जल स्तर घटता है, कई द्वीप जलपक्षी के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करते हैं। अपने विशाल उथले ईख क्षेत्रों के कारण, आर्द्रभूमि को बड़ी संख्या में शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है।

सिरपुर तालाब मध्य प्रदेश के तीसरी रामसर साइट है इसके पहले भोपाल के भोज ताल (बड़ा तालाब) को वर्ष 2002 में तथा शिवपुरी की सांख्य सागर झील को (26 जुलाई 2022 में) रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। सिरपुर तालाब इंदौर में इंदौर-धार रोड पर स्थित है। झील और उसके आसपास के संरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 800 एकड़ (लगभग 3.6 वर्ग किलोमीटर) है और यह इंदौर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिरपुर तालाब का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में इंदौर राज्य के होल्करों द्वारा किया गया था। सिरपुर तालाब रामसर साइट प्रवासी और रहवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है इस साइट पर कुल लगभग 130 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा तालाब को 2015 में मध्य प्रदेश के 19 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी।

सांख्य सागर झील, मध्य प्रदेश

26 जुलाई, 2022 को शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला था। सांख्य सागर झील मध्यप्रदेश का दूसरी रामसर साइट है इसके पहले भोपाल के भोज ताल (बड़ा तालाब) को वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने वर्ष 1918 में मनिहार नदी पर बांधों का निर्माण कराते हुए सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील और माधव तालाब का निर्माण करवाया था। सांख्य सागर झील में पक्षियों के साथ-साथ यहां पर सरीसृपों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में होने की वजह से सांख्य सागर झील के आस-पास काफी मात्रा में वन प्रणियों का भी बसेरा रहता है यही कारण है कि पर्यावरण पर्यटन करने वाले और पर्यावरण पर शोध करने वालों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। रामसर साइट बनने के बाद सांख्य सागर झील पर्यावरण व पक्षी विज्ञानी शोध के लिए नए केंद्र के रूप में भी उभरा क्योंकि शोध करने वालों को ऐसे स्थलों का चयन करते हैं जहां पर जैव विविधता अधिक हो। ऐसे में अब यहां पर देशभर के पर्यावरण व जीव विज्ञानी आकर शोध करने आते हैं।

भोजताल, मध्यप्रदेश

भोज ताल एक बड़ी जलाशय है जो भोपाल के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह शहर के निवासियों के लिए पानीय जल का एक प्रमुख स्रोत है, भोज आर्द्रभूमि का निर्माण करता है, इसी वजह से भोज ताल को अगस्त 2002 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, भोजताल को परमार राजा भोज ने मालवा के राजा (1005-1055) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बनवाया था। लोककथाओं के अनुसार राजा भोज चर्म रोग से पीड़ित हो गए और सभी वैद्य उसका इलाज करने में विफल रहे। फिर एक दिन एक संत ने राजा से कहा कि वह 365 सहायक नदियों को मिलाने के लिए एक तालाब का निर्माण करें और फिर उसमें स्नान करके त्वचा रोग का सफाया करें। भोज ने अपने इंजीनियरों से एक विशाल तालाब बनाने के लिए कहा। जिसके बाद भोज ताल का निर्माण करवाया गया। भोज ताल भोपाल शहर के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है और दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व और उत्तर में मानव बस्तियों और पश्चिम में कृषि क्षेत्रों से घिरा हुआ है। जैव विविधता के लिहाज से देखें, तो सफेद सारस, काली गर्दन वाला सारस, सिर वाला हंस, स्पूनबिल आदि, जो अतीत में दुर्लभ देखे गए हैं। □

रामसर संधि क्या है

रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे इसी संधि या समझौते को रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है इस संधि का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के सभी महत्त्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की सुरक्षा करना है यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है जिसका संरक्षण अति आवश्यक है। आर्द्रभूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है जो मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है और मानव समाज के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता का स्वरस्वाव आदि इसके साथ ही यह क्षेत्र पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी नियंत्रित करता है एवं पानी के प्रवाह की गति को भी कम करता है। भारत आजादी के 75 वें वर्ष में अपनी 75 आर्द्रभूमियों के लिए रामसर मान्यता प्राप्त करने का लक्ष्य को लेकर चल रहा था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है।

नदियाँ दर्शन का अंग हैं ...

नदी भक्ति हम भारतीयों की असाधारण विशेषता है। नदियों को हम 'माता' कहते हैं। इन नदियों से ही हमारी संस्कृतियों का उद्गम और विकास हुआ है। नदी देखते ही उसमें स्नान करना, उसके जल का पान करना और हो सके तो उसके किनारे संस्कृति-संवर्धन के लिए दान देना, यह तीनों प्रवृत्तियां नदी- दर्शन के अंग हैं। स्नान, पान और दान के द्वारा ही नदी पूजा होती है। कई नदी भक्त पुरोहितों की मदद लेकर नदी देवी की शास्त्रोक्त पूजा करते हैं। उसमें 'नदी का ही पानी लेकर नदी को अभिषेक करना' यह क्रिया भी आ जाती है।

ये नदियां या तो किसी पहाड़ से निकलती हैं या किसी सरोवर से निकलती हैं। दूसरे प्रकार की नदियों को 'सरोजा' कहना चाहिए। तब पहले प्रकार की नदियों को 'गिरिजा' ही कहना पड़ेगा। छोटी नदियां बड़ी नदियों को अपना जल देकर उनमें समा जाती हैं और बड़ी नदियां वह सारा विशाल जल समुद्र को अर्पण करके कृतार्थ होती हैं। इसीलिए समुद्र को अथवा सागर को 'नदीपति' कहने का रिवाज़ है।

हम जैसे नदी-भक्त हैं, वैसे ही पहाड़ों के पूजक भी हैं। हमारे कई उत्तमोत्तम तीर्थ पहाड़ों के आश्रय में बसे हुए हैं और जब किसी नदी का उद्गम भी किसी पहाड़ में से होता है तब तो पूछना ही क्या। वह स्थान पवित्रतम गिना जाता है। ऐसे पहाड़ों के, ऐसी नदियों के, ऐसे सरोवरों के और ऐसे समुद्रों के नाम कण्ठ करना और पूजा के समय उनका पाठ करना, यह भी बड़ा पुण्य माना गया है।

जब ऐसे स्थानों के नाम हम कण्ठ करना चाहते हैं तब उनकी संख्या भी हम केवल भक्तिभाव से निश्चित कर देते हैं। एक, तीन, पांच, सात, नौ, दस, बारह, बीस, एक सौ आठ हजार ये सब हमारे अत्यन्त पुण्यात्मक पवित्र आंकड़े हैं। हमारी सारी पृथ्वी को हम 'सप्तखण्डा' कहते हैं। 'सप्त-द्वीपा वसुन्धरा' ये शब्द धर्म-साहित्य में आपको जगह-जगह मिलेंगे। पृथ्वी के खण्ड अगर सात हैं तो उनको घेरने वाले समुद्र भी सात ही होने चाहिए-सप्त सागर। फिर तो भारत की प्रधान नदियां भी सात होनी चाहिए। भारत में नदियां भले ही असंख्य हों, लेकिन हम सात नदियों की ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे पूजा के कलश में अपना-अपना पानी लेकर उपस्थित रहो। भारत में तीर्थ क्षेत्र असंख्य हैं, किन्तु हम लोग उनमें से कण्ठ करने के लिए सात ही नाम पसंद करेंगे और फिर कहेंगे, बाकी के सब तीर्थ-स्थान इन्हीं के पेट में समा जाते हैं।

महीने के दिन निश्चित करने का भार सूर्य और चंद्र ने अपने सिर पर ले लिया और दोनों ने मिलकर हमारा द्वादश मासिक वर्ष भी तैयार किया। हमने एक साल के बारह महीने तुरन्त मान्य किये। द्वादश आंकड़ा है ही पवित्र। फिर महीने के दिन हो गए तीस, लेकिन इसमें दिन का हिसाब थोड़ा-थोड़ा कमोवेश करके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन संभालने ही पड़ते हैं। एक साल के बारह महीने और हरेक महीने के दो पक्ष, हमने तय नहीं किये। यह व्यवस्था कुदरत ने ही हमारे लिए तय कर दी। अब पक्ष के दो विभाग करना हमारे हाथ का था। हम लोगों ने सूर्य-चंद्र के साथ पांच ग्रहों को पसंद करके महीने के चार 'सप्ताह' बना दिये।

हम पूजा में खाने-पीने की चीजें चाहे जितनी रखते होंगे, लेकिन उसके लिए सात धान्यों के ही नाम पसंद करेंगे। हम जानते हैं कि नदियों को जन्म देने वाले बड़े-बड़े आठ

पहाड़ हैं। ऐसे पहाड़ों को हम 'कुलपर्वत' कहते हैं। अष्टकुल पर्वत को मान्य किये बिना चारा ही नहीं था, तो भी सप्तद्वीप, सप्तसरिता, सप्तसागर (उनको 'सप्तार्णव' भी कहते हैं) और सप्तपाताल के साथ पहाड़ों को भी सप्तपर्वत बनना ही पड़ा। सप्तभुवन, सप्तलोक और सप्तपाताल के साथ अपने सूर्य को हमने सात घोड़े भी दिये। हमारी देवियां भी सात। यह तो ठीक, लेकिन गीता, रामायण, भागवत आदि हमारे राष्ट्रीय ग्रन्थों का सार भी हमने सात-सात श्लोकों मे ला रख दिया। सप्तश्लोकी गीता, सप्तश्लोकी रामायण और सप्तश्लोकी भागवत कण्ठ करना बड़ा आसान होता है। आसेतु हिमाचल भारत में तीर्थ की नगरियां असंख्य हैं। ऐसी अनेकानेक नगरियों के माहात्म्य भी लिखे गए हैं। तो भी हम कण्ठ करेंगे :

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका।
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः॥

(माया याने आज का हरिद्वार, पुरी याने जगन्नाथपुरी नहीं, लेकिन द्वारावती ही सातवीं पुरी है।)

भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के प्रति हार्दिक निष्ठा अर्पण करके हमने भारतीय नदियों के अपने इस स्मरण को और उनके उपस्थान को 'सप्तसरिता' नाम दिया। बचपन में जब हमने पिताजी के चरणों में बैठकर भगवान की पूजा-विधि के मंत्र सीख लिये, तब सात नदियों को पूजा के कलश में आकर बैठने की प्रार्थना भी सीख ली थी:

गंगे! च यमुने! चैव गोदावरि! सरस्वति!
नर्मदे! सिंधु! कावेरि! जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु॥

तब नदी भक्ति के हमारे इस नये ढंग के स्तोत्र को 'सप्तसरिता' नाम दिये बिना नदियों को संतोष कैसे हो सकता है?

भारत की नदियों में कृष्णा नदी कोई छोटी नदी नहीं है। उसकी लंबाई, उसके पानी की राशि और उसका सांस्कृतिक इतिहास भारत की किसी भी नदी से कम महत्व का नहीं है। मेरा जन्म इसी नदी के किनारे हुआ। फिर भी ऊपर की सूची में कृष्णा का नाम नहीं है और जिसका रूप और स्थान आजकल कहीं दीख नहीं पड़ता, ऐसी सरस्वती नदी का नाम ऊपर की सूची में मध्यस्थान पर है।

बचपन में और युवावस्था में भी जिसके किनारे मैं खेलता रहा और खेती का परिचय पाने के लिए चलाई हुई मेरी हल चलाने की क्रीड़ा भी जिसने देखी थी, ऐसे छोटे जल-प्रवाह को भले नदी का नाम दो। भारत की सौ-दो-सौ नदियों के नाम में भी जिसको स्थान नहीं मिलेगा, ऐसी छोटी मार्कण्ड नदी को याद किये बिना मेरा काम कैसे चलेगा? उसको याद करते, प्रारंभ में ही मैंने कहा सब नदियों को मैं अपनी माता समझता हूं और मैं उनकी भक्ति भी करता हूं। लेकिन मार्कण्डी को माता नहीं कहूंगा, सखी ही कहूंगा। वह चाहे जितनी छोटी हो, नगण्य हो, मेरी ओर से किये हुए उपस्थान में उसका स्थान होना ही चाहिए। नदियों की फेहरिस्त में नहीं, तो मेरी इस प्रस्तावना में ही, उसे आदर और प्रेम का स्थान दूंगा। अपने सब नदी भक्त पूर्वजों की दलील का उपयोग करके कहूंगा कि भारत की सब नदियां इन सातों के भिन्न-भिन्न अवतार ही हैं। सात की संख्या तो कायम ही रहेगी।

सप्तसरिता की इस आवृत्ति में मेरी भारत-भक्ति से एक नये विचार को स्वीकार किया है। ये नदियां जब पहाड़ की लड़कियां हैं तो उनके उपस्थान में उनके पिता को भी श्रद्धांजलि मिलनी ही चाहिए। पुराणों में अष्टकुल पर्वतों की नामावली और उनकी कन्याओं की फेहरिस्त भी दी है। उनका उल्लेख परिशिष्ट में देकर प्रधानर्तया (1) हिमालय, (2) विंध्य-सतपुड़ा और (3) सह्याद्रि, इन तीन पहाड़ों को ही यहां स्थान दूंगा। (हालांकि महात्मा गांधी का पवित्र सहवास प्राप्त करने के लिए जिस साबरमती नदी के किनारे मैं वर्षों तक रहा, उसके उद्गम का पहाड़ पारियात्र (या अरावली) का नाम-निर्देश किये बिना चारा ही नहीं। यह कोई भूगोल की किताब नहीं है, न यह कोई भारत की नदियों और भारत के पहाड़ों के उपलक्ष्य में लिखी हुई निबन्धमाला है। यह तो सिर्फ अपने देश की प्रतिनिधिरूप लोक-माताओं को भक्तिपूर्वक किया हुआ एक तरह का उपस्थान मात्र है और इन नदियों को सन्तोष हो सके, इस हेतु उनके पिता-स्वरूप भारत के प्रधान तीन-चार पहाड़ों का भक्तिपूर्ण उल्लेख मात्र है।

हमारे पूर्वजों की नदी भक्ति आज भी क्षीण नहीं हुई है। आज भी यात्रियों की छोटी-बड़ी मानव-नदियां अपने-अपने स्थान से इन नदियों के उद्गम, संगम और समुद्र-मिलन की ओर बह-बहकर उसी प्राचीन भक्ति के उतने ही ताजे, सजीव और जाग्रत होने का प्रमाण दे रही हैं। हम हृदय से चाहते हैं कि हरेक भक्त-हृदय इन भक्ति के उद्गारों को सुनकर प्रसन्न हो और देश के युवकों में अपनी लोकमाताओं का दुग्धपान करके अपनी समृद्ध संस्कृति को, और भी पुष्ट करने की अभिलाषा जाग उठे। □

साभार - सप्त सरिता, (पुस्तक)

लेखक - काका सा. कालेलकर

वार्षिक सदस्यता प्रपत्र

मैं ..... एक वर्ष के लिए नर्मदा समग्र त्रैमासिक पत्रिका की सदस्यता लेना चाहता/चाहती हूँ।

4 अंक - वार्षिक शुल्क 100 रूपये, (पोस्टल शुल्क सम्मिलित)

नाम : _____ लिंग : _____

कार्य : व्यवसाय ☐ कृषि ☐ नौकरी ☐ विद्यार्थी ☐ संगठन ☐

संस्था : _____ दायित्व/पद : _____

फोन : _____ मोबाइल : _____ ई-मेल : _____

पता : _____

जिला : _____ पिन कोड : _____ राज्य : _____

भुगतान विवरण : चेक/डिमांड ड्राफ्ट नं. : _____ दिनांक : _____ रूपये : _____

अदाकर्ता बैंक : _____ शाखा : _____

खाते की जानकारी (ऑन लाईन भुगतान हेतु)

Narmada Samagra
State Bank of India
Shivaji Nagar Branch, Bhopal, M.P.
Ac no. 30304495111
IFSC: SBIN0005798

दिनांक : _____ हस्ताक्षर : _____

"नदी का घर"
सीनियर एमआईजी -2, अंकुर कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश - 462016
दूरभाष + 91-755-2460754 ई-मेल : narmada.media@gmail.com

नदियों की पवित्रता की रक्षा का संकल्प लें, स्वयं से प्रारंभकर, समुदाय को प्रेरित करें
रक्षाबंधन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं...

नर्मदा समग्र शंकर घाट टोली, डिंडौरी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री, भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कलश (नर्मदा जल) को रक्षासूत्र बांधकर जल संरक्षण का संकल्प लिया।

नर्मदा समग्र ग्वारीघाट टोली द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम में जनअभियान परिषद प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जितेन्द्र जामदार और जबलपुर के महापौर श्री जगत बहादुर सिंह (अन्नू भैया) द्वारा कलश (नर्मदा जल) को रक्षासूत्र बांधकर नर्मदा जल संरक्षण का संकल्प लिया।

नदी एम्बुलेंस कार्यक्षेत्र (सरदार सरोवर डूब क्षेत्र) म.प्र. एवं महाराष्ट्र के फलियों में वनवासी भाई-बहनों द्वारा वृक्षों को और मां नर्मदा का जल कलश में लेकर, रक्षा सूत्र बांधकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान के लिए उत्साहित कार्यकर्ताओं द्वारा फलियों में वितरण हेतु तिरंगे उपलब्ध कराए गए। ग्रामवासियों ने अपने घर तिरंगा लहराया।

सहस्त्र डोल - शहडोल

फायदे का सौदा तो अभी भी है। यदि इनके मौसमी और दीर्घकालीन फायदे के बारे में विचार मंथन किया जाये, इतनी बड़ी संख्या में इन तालाबों की उपस्थिति अनेक तरह की जलीय वनस्पतियों को स्थान उपलब्ध कराती है।

संतोष शुक्ला

(लेखक - वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

मध्यप्रदेश का शहडोल जिला आदिवासी संस्कृति, पर्यावरण, खनिज भण्डार वन्य जीवो आदि के लिये जाना जाता है। इन सभी के अलावा शहडोल जिले की एक विशेष पहचान अभी तक देश दुनिया की नजरों के सामने नहीं आ सकी है।

यह पहचान है, एक छोटे से नगर जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 03 किलोमीटर है, इतने छोटे से क्षेत्र में आज भी लगभग 195 तालाबों का होना। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां इतने सघन तालाबों की श्रृंखला आज भी विद्यमान होगी।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कि आखिर इतने तालाब किसलिये और क्यों बनाये गये होगे। इस विषय में शोध करने पर कई कारण सामने आते है। जिनमें एक तो यह है, कि भारत में जल संरचना के निर्माण को पुण्य कार्य से जोड़ा जाता है। इसलिये यहां के राजाओं ने तालाबों और बाबड़ियों का निर्माण कराया होगा, दूसरा कारण इसके व्यवसायिक इस्तेमाल का है। इन तालाबों में सिंघाड़े की खेती होती थी, जिससे राज्य को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता था।

एक अन्य कारण यह भी पता चलता है, कि शहडोल जिले से कई शताब्दियों पहले से वनोपज का व्यवसाय किया जाता रहा है। उस समय वनोपज को मंडियो तक बैलगाड़ी के माध्यम से भेजा जाता था। एक व्यापारी के पास सौ से अधिक बैलगाड़ियॉ होती थी। हर बैलगाड़ी में दो बैल उसका चालक और एक सहायक चलता था। जिस समय बैलगाड़ियां अपने सेठ के यहां होती बैलों को नहलाने, पानी पिलाने के लिये भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिये व्यापारियों ने बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण कराया। इस तरह तालाब निर्माण व्यापारियों के लिये दोहरे फायदे का सौदा था।

फायदे का सौदा तो अभी भी है। यदि इनके मौसमी और दीर्घकालीन फायदे के बारे में विचार मंथन किया जाये, इतनी बड़ी संख्या में इन तालाबों की उपस्थिति अनेक तरह की जलीय वनस्पतियों को स्थान उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही मेंढ़कों, कीटकों, मछलियॉ, तितलियों को भी प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराती है। ठंड के दिनों में चुनिन्दा प्रवासी पक्षी भी हर वर्ष इन तालाबों का रुख करते है। क्योंकि यहां उन्हें भोजन और प्रजनन की सुविधा प्राप्त होती है। इनमें से ज्यादातर पक्षी सेमी माइग्रेटरी या हिमालयन पक्षी है। जिनमें से बर्ड ईटर फ्लाई कैचर, बाहमी डक, स्टोन चैट वर्ड (साइवेरियन) प्रमुख है।

यह इस शहर का दुर्भाग्य ही है, कि यहां के रहवासियों की उपेक्षा का शिकार ये तालाब अपनी सबसे खराब अवस्था में पहुँच गये है। कुछ तालाबों का सरकार द्वारा संरक्षण भी किया गया है। परन्तु इस कीमती खजाने के लिये यह कदम पर्याप्त नहीं है।

अधिकतर तालाबों में अतिक्रमण कर लिया गया है। शहर में ऐसे कई घर है, जो बीच तालाब में बने हुये है। जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। शहडोल नगर में पटेल धर्मशाला के पीछे एक घर आज भी देखा जा सकता है। बहुत सारे तालाब अंतिम सांसे इसलिये गिन रहे है, वर्षो पहले जिला प्रशासन ने इन तालाबों की मेड़ो को लोगों को लीज पर दे दिया। आज ये निर्माण लीज से दो गुनी भूमि पर पहुँच गये है। यह जानकर आश्चर्य होता है, कि एक समय बहुत सारे सरकारी कार्यालयों, हॉस्टल, अन्य सरकारी भवनों के लिये तालाबों की जमीन (अलाट) या कहे कि तालाबों को ही (अलाट) कर दिया गया। तालाबों को पाटकर निर्माण कार्य कर लिये गये। शहर में तीन हाउसिंग बोर्ड की कालोनियॉ है, तीनों तालाबों को पाटकर बनायी गयी है। किसी भी नगर के भविष्य के लिये यह निर्णय कितने गलत है, यह तो भविष्य बताएगा ही। तालाबों को पाटकर कालोनियॉ, आफिस बनाने की योजना तब बनाई गयी थी जब शहर के चारों ओर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध थी।

जब शहर के संपन्न लोगो ने तालाबों पर अतिक्रमण की शुरुआत की तो गरीब कहां पीछे रहते। पिछले कई दशकों में शायद ही कोई तालाब बचा होगा, जिसकी पूरी की पूरी मेंड़ अतिक्रमण का शिकार हो गयी हो। अतिक्रमण ने एक नयी समस्या को जन्म दिया तालाबों में साफ पानी की जगह इन बसाहटो का जलमल भर गया। अतिक्रमण के पहले तालाब जैव विविधता का खजाना थे। आज घरों के गंदे पानी से भरे हुये है। इस पानी की वजह से जलीय जीवों का जीवन समाप्त प्रायः है। रही सही कसर तालाबों में वर्षो से जमा गाद ने पूरी कर दी हैं जिसके कारण तालाब की पानी संधारण की क्षमता निम्नतर स्तर पर पहुँच गयी है। □

पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन से...

शोषक नहीं, पोषक हैं हम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेषता यह है कि वे अल्पकालीन नीतियों पर काम नहीं करते, बल्कि दीर्घकालीन योजना और उनसे पड़ने वाले प्रभाव पर नजर रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय पर उनके विजन में भी इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। जहां एक ओर वे देश में कृषि को पारंपरिक और जलवायु के मुताबिक ढलने वाली बनाने पर जोर देते हैं तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक मंचों पर पर्यावरण संरक्षण के साथ जलवायु न्याय की बात मजबूती से उठाते हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर वे गंभीर रहे हैं तो वहीं कचरा प्रबंधन के जरिए पर्यावरण को नुकसान से बचाने पर भी उनका बराबर जोर रहा है। एक ओर वे औद्योगिक क्रांति 4.0 पर अपना विजन सामने रखते हैं तो दूसरी ओर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के मंत्र के साथ भारत की परंपरा और विरासत का जिक्र करना वे नहीं भूलते। 23 सितंबर को गुजरात में आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में एक बार फिर उन्होंने पर्यावरण के साथ विकास पर अपनी विचारधारा को किया साझा...

आज का नया भारत, नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकॉनमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है और वेटलैंड का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में हमारी स्पीड और हमारी स्केल तक शायद ही कोई पहुंच सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सीडीआरआई (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) या फिर लाइफ (Lifestyle for environment) मूवमेंट.. बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के भारत के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बीते 8 वर्ष में भारत के नजरिये के इन्हीं बदलावों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किया। उन्होंने, ''भारत के लोग कभी प्रकृति के शोषक नहीं बल्कि पोषक रहे हैं। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है।'' प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की, ''हम एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है, आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा।''

प्रधानमंत्री ने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह किया। ऐसा करने से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन में पर्यावरण क्लीयरेंस देने में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने पर्यावरण मंत्रियों से स्पष्ट किया, ''आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लीयरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टिट्यूशन, कई फाउंडेशंस भी विषय पकड़ कर तूफान खड़ा कर देते हैं। ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर नाचते रहते हैं और हमारे यहां रूकावट आ जाती हैं। हमें ऐसे विषयों में समग्र सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लीविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करें।'' □

आओ बनाएं अपने हाथों अपने श्री गणेश

महाकौशल भाग में आओ बनाएँ मिट्टी के श्रीगणेश कार्यशाला की झलकियां

नर्मदा समग्र द्वारा स्वामी मोहनानंद हाईस्कूल, तलून, बड़वानी में आओ बनाएं अपने हाथों अपने श्री गणेश कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 100 छात्र-छात्राओं मिट्टी से श्रीगणेश बनाने का प्रशिक्षण लिया।

''नदी का घर'' गणेशोत्सव की झलकियाँ...

'आओ बनाये अपने हाथों अपने श्री गणेश' मूर्ति प्रशिक्षण कार्यशाला में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के डिप्टी डायरेक्टर श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी ने मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण लिया।

''नदी का घर'' ईको फ्रेण्डली मूर्ति प्रशिक्षण कार्यशाला की झलकियां

दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन ने ''आओ बनाएँ अपने हाथों अपने श्रीगणेश'' कार्यशाला में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों से चर्चा की एवं उनका उत्साहवर्धन किया।

नर्मदापुरम भाग में आओ बनाएँ मिट्टी के श्रीगणेश कार्यशाला की झलकियां

हरियाली चुनरी

नर्मदा के दक्षिण तट डालखेड़ा (कसरावद) में 101 पौधों की हरियाली चुनरी का रोपण के लिए
श्री शैलेन्द्र शर्मा जी, अध्यक्ष कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा किया गया।

नर्मदा समग्र कार्यकर्ता केशव सोनवानी एवं साथियों ने कलगी टोला घाट, जिला डिंडौरी में 110 पौधों का रोपण किया गया।
इनमें आम, नीम, जामुन, अर्जुन, करंज, बिही के पौधे हैं, इन पौधों के सुरक्षा की चिंता भी की गयी है।

RNI No. - MPHIN/2011/38276

मोदी जी का जन्मदिन,
चीतों की सौगात।
खुश है मध्यप्रदेश और,
पुलकित है गुजरात।
सत्तर सालों में नहीं,
हो पाया जो काम।
आज देश ने उसे भी,
दे डाला अंजाम।
नामीबिया से हो रही,
चीता फैमिली शिफ्ट।
दुर्लभ यह इवेंट है,
गजब वर्थडे गिफ्ट।
बरसों की तैयारियां,
अध्ययन और प्रयास।
कुनो पालपुर में नया,
लिखा गया इतिहास।
बनी रहे उपलब्धि यह,
कभी न बिगड़े लय।
ऐसे ही होती रहे,
वन विभाग की जय।

- डॉ. पंकज श्रीवास्तव

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्री करण सिंह कौशिक द्वारा नियो प्रिंटर्स, 17 बी-सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल एवं नदी का घर सीनियर एम.आई.जी.-2 अंकुर कॉलोनी, पारूल अस्पताल के पास शिवाजी नगर, भोपाल-462016 से प्रकाशित। संपादक कार्तिक सप्रे। फोन नं. : 0755-2460754